

संख्या - ४०४/१/२०८.

संख्या-

/XVIII(II)/2016-18(41)/2016

प्रेषक,

डी०एस० गव्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-2

A.S.(S)

संख्या ३७..... २०४/१/२०८ / 2016

देहरादून : दिनांक १७/१०/२०८ / 2016

सचिव  
उत्तराखण्ड प्रशासन  
चौमध्ये सम्पूर्ण प्रान्तम्।

देहरादून: दिनांक ०५/०५/२०८ / 2016

विषय:- जनपद अल्मोड़ा बैडमिन्टन कोर्ट निर्माण हेतु खेल विभाग को 1.202 हौ० भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

A.S.(S)

१५/८/१६

अपर सचिव,  
युवा कल्याण विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

उपरोक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-1639/पांच-  
भू०ह०ग००५०-०१६ दि०-२२.०६.२०१६ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल  
ग्राम एवं पटवारी क्षेत्र देवली, तहसील एवं जनपद अल्मोड़ा के गैर ज०वि०ख०खा० सं०-८० की  
श्रेणी-१०(२) अकृषक भूमि के खेत सं०-९४५ मध्ये ०.२२१ हौ० ९४७ मध्ये ०.०४१ हौ० गैर ज०वि० ख०  
खा० सं०-६२ की श्रेणी-९(३)ग स्थायी पशुचर/गौचर के खेत सं०-९४६ की ०.१३९ हौ० ९४८ की ०.  
६०२ हौ० ९५९ की ०.०७० हौ० १०२२ की ०.१२९ हौ० इस प्रकार कुल १.२०२ हौ० प्रस्तावित की गयी है।  
ग्राम देवली में स्थाई पशुचर की भूमि का कुल क्षेत्रफल ४५.६०२ हौ० है। जिसमें से ०.९४० हौ० भूमि के  
चयनित किया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु चयनित की गयी गौचर की भूमि के हस्तान्तरण के  
पश्चात उक्त ग्राम में कुल ४४.६६२ हौ० गौचर की भूमि अवशेष रहेगी। जो कि कुल भूमि का ५  
प्रतिशत से अधिक है, को वित्त अनुभाग-३ के शासनादेश सं०-२६०/वित्त अनुभाग-३/२००२  
दि०-१५.०२.२००२ के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत खेल विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो  
और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके  
लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए  
उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु  
किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना  
भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष  
पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन  
गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी  
से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

नॉन जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- 9— इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं०-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि०-जनवरी, 2011 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गर्वाल)  
सचिव।

पू०प०संख्या-/८३/XVIII(II)/2016-18(41)/2016 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— सचिव, खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।  
2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।  
3— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।  
4— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।  
5— विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

राज्य  
(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव।